राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

एफ29 (20)एनआरएचएम/एमएमजेआरके/जयपुर I/कोर्ट केस/11/4289 दिनांक 24/10/2011

समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी

.....

विषयः– SBCWPNo. 5508/2011 श्री अनिल कुमार पटवा व अन्य के साथ 83 रिट पिटिशन बनाम राज्य सरकार व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय राज. जयपुर के आदेश दिनांक 20.9.2011 के तहत कार्यवाही करने बाबत।

महोदय,

माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा रिट पिटीशन 5508/11 श्री अनिल कुमार पटवा व अन्य बनाम राज्य सरकार व अन्य के प्रकरण में पारित आदेश को संलग्न कर आपको भिजवाया जा रहा है इस पर निम्नांकित कार्यवाही सम्पादित करके, आपके जिले की अनुपालना रिर्पोट दिनांक 1.11.2011 तक आवश्यक रूप से परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष को भिजवाना सुनिश्चित करावे।

1. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा के स्वीकृत पदों को छोड़कर अन्य सभी कार्मिकों को जिन्होंने माननीय उच्च न्यायालय जयपुर/जोधपुर में रिट दायर की है तथा जिनकी रिट याचिकाये खारिज की जा चुकी है उन्हें तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये। स्वीकृत पदों की सूची वर्ष 2010–11 की संलग्न है, तथा विभागीय वेब साईट www.cmbpljrk.raj.nic.in पर भी उपलब्ध है।
2. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के संविदा कार्मिक जिनका मिशन निदेशक, एनआरएचएम की सक्षम स्वीकृति के बिना मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी ने एनआरएचएम में अपने स्तर से ही समायोजित कर दिया था तथा जिनकी रिट याचिकायें दिनांक 20.9.2011 को खारिज की जा चुकी है तथा जिनके संविदा पद स्वीकृत नहीं है उनको तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये।
3. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत कुछ कम्प्यूटर ऑपरेटर्स जिनके पद वित्त विभाग से स्वीकृत होने के बावजूद भी उन्होने एनआरएचएम में समायोजन होने के लिए रिट याचिका माननीय उच्च न्यायालय में दायर की थी माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.9.2011 के तहत जिनकी रिट याचिकायें खारिज की जा चुकी है उन्हें मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना में अगर पद स्वीकृत व रिक्त है तो कार्य पर रखा जावे अन्यथा उसे तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये। कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर्स को मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष के तहत स्वीकृत मानदेय ₹ 4,500 का ही भुगतान किया जाये।
4. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना का फार्मासिस्ट जिसकी रिट याचिका दिनांक 20.9.2011 के आदेश से खारिज की जा चुकी है एवं वे फार्मासिस्ट जिनका मिशन निदेशक, एनआरएचएम की बिना सक्षम स्वीकृति के मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा एनआरएचएम में समायोजन कर दिया है उनकों अगर मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष में पद स्वीकृत है तो यथावत कार्यरत रखकर उसे मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष का मानदेय ₹ 4,500 दिया जाये अन्यथा उसे तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये।
5. लिपिक एवं वार्ड ब्वाय के पद मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना में स्वीकृत नहीं है। अतः मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष व इसी योजना के एनआरएचएम में मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी द्वारा समायोजित किये गये लिपिक व वार्ड ब्वाय जिनकी रिट पिटिशन माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 20.9.2011 के तहत खारिज की जा चुकी है। ऐसे संविदा कर्मियों को तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जाये।
6. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष में संविदा कार्मिकों के स्वीकृत पदों हेतु माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 20.9.2011 को पारित आदेश में **"last come - first go"** के सिद्वांत की पालना किया जाना आवश्यक है।

7. मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के जिन संविदा कार्मिकों की रिट पिटिशन खारिज की जा चुकी है उन्हें माननीय उच्च न्यायालय जयपुर के आदेशानुसार कार्यवाही करके तुरन्त हटाया जायें। मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना से इन कार्मिकों के मानदेय का भुगतान 31.10.2011 तक ही करे, अगर किसी चिकित्सा संस्थान प्रभारी द्वारा इस तिथि के बाद भी उक्त संविदा कार्मिकों को कार्यरत रखा जाता है तो इन्हे मानदेय का भुगतान तथा अन्य न्यायिक कार्यवाही के लिए उसकी व्यक्तिगत जिम्मेदारी होगी।
8. माननीय उच्च न्यायालय जयपुर द्वारा दिनांक 20.09.2011 को पारित आदेश के तहत शेष जिन रिट पिटिशन पर निर्णय होना बकाया है उनके बाबत सम्बंधित ओ.आई.सी. को तुरन्त अधिवक्ता से सम्पर्क कर प्रकरण का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 20.9.2011 के अनुरूप करवाने का प्रयास करावे एवं माननीय उच्च न्यायालय जयपुर में डीबी स्पेशल अपील दायर किये जाने की सम्भावना को द्वष्टिगत रखते हुए प्रकरण के संबंध में श्री विभूति भूषण शर्मा एडिशनल गवर्नमेंट कौंसलि राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर से सम्पर्क कर शीघ्र केवियट फाइल करने की कार्यवाही करावे।

संलग्न– उपरोक्तानुसार

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपी निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है। –

1. निजी सचिव, महाधिवक्ता, राजस्थान उच्च न्यायालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, शासन सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, विशिष्ठ शासन सचिव व मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
4. समस्त प्रधानाचार्य, मेडिकल कॉलेज, राजस्थान/समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज से संबद्ध चिकित्सालय, राजस्थान/समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला चिकित्सालय, राजस्थान /समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी उप खण्ड/सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान/समस्त चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, राजस्थान भेजकर लेख है कि आपके चिकित्सा संस्थान में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के जिन संविदा कर्मियों द्वारा माननीय उच्च नयायालय में रिट पिटिशन दायर की गयी है उनका निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के अनुसार करवाने की कार्यवाही करके उसकी सूचना जिला मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के माध्यम से शीघ्र परियोजना निदेशक मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष को भिजवाने का श्रम करे।
5. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
6. वित्तीय सलाहकार, एनआरएचएम, जयपुर।
7. उप अधीक्षक, मनौचिकित्सालय, जयपुर।
8. उपविधि परामर्शी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाऐं जयपुर।
9. श्री विभूति भूषण शर्मा, एडिशनल गवंरमेंट कॉसिल, जयपुर।
10. संबंधित केस प्रभारी अधिकारी को पत्र भेजकर लेख है कि आपके अधीन बचे हुए कोर्ट केसों का जवाबदावा तैयार कर श्रीमती मंजू जैन अधिवक्ता/श्री यशपाल खिलेरी डिप्टी गवर्नमेंट कौंसलि से सम्पर्क कर उक्त निर्णय के अन्तर्गत कोर्ट केस निस्तारण कराने का श्रम करे।
11. श्रीमती मंजू जैन, अधिवक्ता राजस्थान उच्च न्यायालय जयपुर को पत्र भेजकर लेख है कि राज. उच्च न्यायालय जयपुर के आदेश दिनांक 20.9.2011 के शेष लम्बित रिट पिटिशन का निस्तारण माननीय उच्च न्यायालय, जयपुर द्वारा दिनांक 20.9.2011 को पारित आदेश के अनुसार कराने का श्रम करे।
12. श्री यशपाल खिलेरी, डिप्टी गवरमेंट कॉसिल राजस्थान उच्च न्यायालय जोधपुर।
13. प्रभारी सेन्टर सर्वर रूम को पत्र भेजकर लेख है कि कृपया संबंधित को ई–मेल कराने का श्रम करावे।
14. गार्ड फाईल।

मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

सही [illegible] प्रतिलिपि [illegible]
पत्र सं. [illegible]
दिनांक [illegible]

प्रशासनिक अधिकारी [illegible]
प्रतिलिपि विभाग,
राजस्थान उच्च न्यायालय, [illegible]

Certified Copy of Order dated 20/9/11

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN

AT JAIPUR BENCH, JAIPUR.

11760
19-9-11

S.B. CIVIL WRIT PETITION NO. 5508 /2011

Anil Kumar Patwa son of Shri Chirangi Lal Patwa, aged about 24 years, resident of Plot No.C-105, Shekhawati Nagar, Road, No.6, VKI Area, Sikar Road, Jaipur.

...Petitioner.

Versus.

1- State of Rajasthan through Principal Secretary, Medical and Health Department, Government of Rajasthan, Secretariat, Jaipur.

2- Mission Director, National Rural Health Mission, Headquarter, Medical and Health Services, "Swasthya Bhawan', Tilak Marg, Jaipur.

3- Project Director, Chief Minister B.P.L. Jeevan Raksha Kosh, Directorate of Medical and Health Services, "Swasthya Bhawan', Tilak Marg, Jaipur.

4- Chief Medical and Health Officer, Jaipur.

5- Superintendent, Mental Hospital, Jaipur.

...Respondents.

सत्यमेव जयते

सही – प्रतिलिपि

OATH COMMISSIONER
Rajasthan High Court Bench
JAIPUR

WRIT PETITION UNDER ARTICLE 226

OF THE CONSTITUTION OF INDIA

AND

IN THE MATTER OF ARTICLES 14, 16 AND 21

OF THE CONSTITUTION OF INDIA.

AND

IN THE MATTER OF CHIEF MINISTER, B.P.L.

JEEVAN RAKSHA KOSH

AND

IN THE MATTER OF NATIONAL RURAL HEALTH

MISSION.

To,

IN THE HIGH COURT OF JUDICATURE FOR RAJASTHAN

JAIPUR BENCH, JAIPUR

ORDER

1. SB Civil Writ Petition No. 5508/2011
Anil Kumar Patwa Vs State of Rajasthan & ors

2. SB Civil Writ Petition No.11163/2011
Azad Singh Versus State of Rajasthan & ors

3.SB Civil Writ Petition No.7810/2011
Pawan Kumar Sharma & ors Versus State of Rajasthan & ors

4.SB Civil Writ Petition No.8673/2011
Shiv Raj Singh Rathore & ors Versus State of Rajasthan & ors

5.SB Civil Writ Petition No.3238/2011
Ashok Kumar Jangid & ors Versus State of Rajasthan & ors

6.SB Civil Writ Petition No.3239/2011
Dilip Kumar Saini & ors Versus State of Rajasthan & ors

7.SB Civil Writ Petition No.3574/2011
Ganesh Ram Versus State of Rajasthan & ors

8.SB Civil Writ Petition No.3764/2011
Dinesh Saini Versus State of Rajasthan & ors

9.SB Civil Writ Petition No.3998/2011
Balram Sharma & ors Versus State of Rajasthan & ors

10.SB Civil Writ Petition No.4233/2011
Amit Saini Versus State of Rajasthan & ors

11.SB Civil Writ Petition No.4390/2011
Mukesh Kumar Saini Versus State of Rajasthan & ors

12.SB Civil Writ Petition No.4520/2011
Ganpat Kumar Sharma & ors Versus State of Rajasthan & ors

13.SB Civil Writ Petition No.4731/2011
Yogesh Sharma Versus State of Rajasthan & ors

14.SB Civil Writ Petition No.4943/2011

Kailash Chand Sherawat Versus State of Rajasthan & ors

15.SB Civil Writ Petition No.4944/2011
Mukesh Tak Versus State of Rajasthan & ors

16.SB Civil Writ Petition No.5455/2011
Arjun Lal Jat Versus State of Rajasthan & ors

17.SB Civil Writ Petition No.5478/2011
Shivraj Singh Rathore Versus State of Rajasthan & ors

18.SB Civil Writ Petition No.5509/2011
Kajod Ram Saini Versus State of Rajasthan & ors

19.SB Civil Writ Petition No.5510/2011
Lokesh Jain Versus State of Rajasthan & ors

20.SB Civil Writ Petition No.5992/2011
Rajbeer Singh Versus State of Rajasthan & ors

21.SB Civil Writ Petition No.6000/2011
Prem Chand Sharma Versus State of Rajasthan & ors

22.SB Civil Writ Petition No.6100/2011
Gautam Krishan Sharma Versus State of Rajasthan & ors

23.SB Civil Writ Petition No.6101/2011
Mahendra Kumar Sharma Versus State of Rajasthan & ors

24.SB Civil Writ Petition No.6626/2011
Shish Ram Gurjar & ors Versus State of Rajasthan & ors

25.SB Civil Writ Petition No.6627/2011
Mukut Swaroop Sharma & ors Versus State of Rajasthan & ors

26.SB Civil Writ Petition No.6666/2011
Chandra Kumar Versus State of Rajasthan & ors

27.SB Civil Writ Petition No.6702/2011
Rajesh Kuma Saini Versus State of Rajasthan & ors

28.SB Civil Writ Petition No.6882/2011
Deva Ram Saharan Versus State of Rajasthan & ors

29.SB Civil Writ Petition No.7000/2011
Rajesh Patidar Versus State of Rajasthan & ors

30.SB Civil Writ Petition No.7001/2011

सत्यमेव जयते
जयपुर
प्रतिलिपि

Lokesh Kumar Suthar Versus State of Rajasthan & ors

31.SB Civil Writ Petition No.7002/2011
Devendra Kumar Prajapati Versus State of Rajasthan & ors

32.SB Civil Writ Petition No.7224/2011
Ramesh Kumar Versus State of Rajasthan & ors

33.SB Civil Writ Petition No.7239/2011
Dinesh Kumar Sharma Versus State of Rajasthan & ors

34.SB Civil Writ Petition No.7300/2011
Surendra Saini & ors Versus State of Rajasthan & ors

35.SB Civil Writ Petition No.7398/2011
Smt Komal Kalal Versus State of Rajasthan & ors

36.SB Civil Writ Petition No.7464/2011
Inderlal Guru Versus State of Rajasthan & ors

37.SB Civil Writ Petition No.7465/2011
Shyam Singh Versus State of Rajasthan & ors

38.SB Civil Writ Petition No.7498/2011
Krishan Lal Versus State of Rajasthan & ors

39.SB Civil Writ Petition No.7484/2011
Vachnaram Versus State of Rajasthan & ors

40.SB Civil Writ Petition No.7627/2011
Hans Raj Gurjar & ors Versus State of Rajasthan & ors

41.SB Civil Writ Petition No.7641/2011
Dinesh Kumar Gautam Versus State of Rajasthan & ors

42.SB Civil Writ Petition No.7663/2011
Alok Solera Versus State of Rajasthan & ors

43.SB Civil Writ Petition No.7687/2011
Karan Singh Jat Versus State of Rajasthan & ors

44.SB Civil Writ Petition No.7688/2011
Mahaveer Prasad Meena Versus State of Rajasthan & ors

45.SB Civil Writ Petition No.7703/2011
Jitendra Singh Choudhary Versus State of Rajasthan & ors

46.SB Civil Writ Petition No.7714/2011

सत्यमेव जयते
जयपुर
सही – प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक,
राज० उच्च न्यायालय पी.ठ,
जयपुर

Mahendra Kumar Goyal Versus State of Rajasthan & ors

47.SB Civil Writ Petition No.7716/2011
Bodilal Jat & ors Versus State of Rajasthan & ors

48.SB Civil Writ Petition No.7744/2011
Surendra Peepliwal Versus State of Rajasthan & ors

49.SB Civil Writ Petition No.7809/2011
Lalit Kishore Yadav & ors Versus State of Rajasthan & ors

50.SB Civil Writ Petition No.7811/2011
Chandra Prakash Soni & ors Versus State of Rajasthan & ors

51.SB Civil Writ Petition No.8303/2011
Pushpendra Singh Versus State of Rajasthan & ors

52.SB Civil Writ Petition No.8346/2011
Kailash Kumar Sharma Versus State of Rajasthan & ors

53.SB Civil Writ Petition No.8347/2011
Hitendra Kumar Dave Versus State of Rajasthan & ors

54.SB Civil Writ Petition No.8373/2011
Sandeep Kumar Sharma & ors Versus State of Rajasthan & ors

55.SB Civil Writ Petition No.8416/2011
Satish Kumar Jeengar & anr Versus State of Rajasthan & ors

56.SB Civil Writ Petition No.8493/2011
Ailkar Singh & ors Versus State of Rajasthan & ors

57.SB Civil Writ Petition No.8528/2011
Sanjay Sharma Versus State of Rajasthan & ors

58.SB Civil Writ Petition No.8546/2011
Choutha Ram & anr Versus State of Rajasthan & ors

59.SB Civil Writ Petition No.8532/2011
Vinod Kumar Versus State of Rajasthan & ors

60.SB Civil Writ Petition No.8547/2011
Randhir Singh & ors Versus State of Rajasthan & ors

61.SB Civil Writ Petition No.9036/2011
Abhishek Jain Versus State of Rajasthan & ors

62.SB Civil Writ Petition No.9079/2011

सत्यमेव जयते
जयपुर
सही – प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी (न्यायिक),
राज० उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

Mahendra Kumar Sharma Versus State of Rajasthan & ors

63.SB Civil Writ Petition No.9123/2011
Madhu Krishan Sharma Versus State of Rajasthan & ors

64.SB Civil Writ Petition No.9221/2011
Smt Sajna Devi Versus State of Rajasthan & ors

65.SB Civil Writ Petition No.9284/2011
Heetendra Singh Gurjar Versus State of Rajasthan & ors

66.SB Civil Writ Petition No.9328/2011
Satyendra Kumar Nagar Versus State of Rajasthan & ors

67.SB Civil Writ Petition No.9437/2011
Satish Kumar Gupta & anr Versus State of Rajasthan & ors

68.SB Civil Writ Petition No.9645/2011
Krishan Chandra Versus State of Rajasthan & ors

69.SB Civil Writ Petition No.9785/2011
Mahendra Sharma Versus State of Rajasthan & ors

70.SB Civil Writ Petition No.9882/2011
Mohammad Khalid Khan & ors Versus State of Rajasthan & ors

71.SB Civil Writ Petition No.10322/2011
Surendra Kumar Sharma Versus State of Rajasthan & ors

72.SB Civil Writ Petition No.10375/2011
Rajesh Kumar Versus State of Rajasthan & ors

73.SB Civil Writ Petition No.10462/2011
Nirmal Versus State of Rajasthan & ors

74.SB Civil Writ Petition No.10751/2011
Sudheer Kumar Jain Versus State of Rajasthan & ors

75.SB Civil Writ Petition No.10975/2011
Neha Bakliwal Versus State of Rajasthan & ors

76.SB Civil Writ Petition No.11164/2011
Mohit Kumar Gupta Versus State of Rajasthan & ors

77.SB Civil Writ Petition No.11166/2011
Mohd. Asif Khan Versus State of Rajasthan & ors

78.SB Civil Writ Petition No.11167/2011

सत्यमेव जयते
जयपुर

सही – प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक,
राज० उच्च न्यायालय पी.ठ,
जयपुर

Pradeep Chand Goyal Versus State of Rajasthan & ors

79.SB Civil Writ Petition No.11169/2011
Raj Kumar Sain Versus State of Rajasthan & ors

80.SB Civil Writ Petition No.11170/2011
Lakhan Lal Versus State of Rajasthan & ors

81.SB Civil Writ Petition No.11171/2011
Namo Narayan Sharma Versus State of Rajasthan & ors

82.SB Civil Writ Petition No.11249/2011
Jagdish Prasad Rathore Versus State of Rajasthan & ors

83.SB Civil Writ Petition No.11498/2011
Girdhari Lal Jat Versus State of Rajasthan & ors

84.SB Civil Writ Petition No.11880/2011
Roshan Lal Sain Versus State of Rajasthan & ors

20.9.2011

HON'BLE MR. JUSTICE MN BHANDARI

Mr SP Sharma, Sr Adv with Mr SS Shekhawat
Mr Anil Kumar Sharma
Mr Amardeep Atwal
Mr Atmaram Meena
Mr RP Saini
Mr Krishan Sharma
Mr Manish Kumar
Mr RS Bhardwaj
Mr SK Singodiya
Mr Praveen Sharma
Mr Suresh Dhenwal
Mr Liyakat Ali
Mr Bharat Saini
Mr Sandeep Garssa - for the petitioners

Mr GS Bapna, Advocate General with Mr Venkatesh Garg

सत्यमेव जयते
जयपुर
सही – प्रतिलिपि

Mrs Manju Jain – for National Rural Health Mission
Dr VB Sharma, Addl Government Counsel – for respondents

BY THE COURT:

With consent of the parties, all the writ petitions have been finally heard. Since on same set of facts, similar relief has been prayed, all these writ petition are decided by this common order.

Learned counsel submit that petitioners were appointed by the respondents on various posts like Accountant, Junior Ayurved Nurse/ Compounder, Computer Operator, Block Asha Facilitator, Pharmacist, PHC Asha Supervisor etc under the Chief Minister Below Poverty Line Jeevan Raksha Kosh Scheme (for short 'BPL Jeevan Raksha Kosh'). They were given appointment on contract basis. While petitioners were discharging their duties continuously, a short term advertisement dated 6.9.2010 at Annexure-2 in CW No.5508/2011, inviting applications for the posts held by the petitioners, was issued by the respondents under the National Rural Health Mission (for short the NRHM'). Apprehending termination, various writ petitions were filed, which were then decided by this court, wherein, few petitions/ appeals were dismissed and in other appeals, a direction was issued to consider case of the petitioners in the light of the

सत्यमेव जयते
जयपुर
सही – प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक,
राज० उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

circular dated 9.8.2010 at Annexure-3. The aforesaid circular provides for continuance of those engaged in BPL Jeevan Raksha Kosh Scheme against the posts in NRHM. After the judgment in appeal by the Division Bench on 19.1.2011, respondents issued order dated 4.2.2011 at Annexure-5 deleting condition No.8 of the circular dated 9.8.2011, thereby, those engaged in BPL Jeevan Raksha Kosh Scheme were not to be adjusted in NRHM. Petitioners were informed about the aforesaid by the office order dated 10.2.2011 at Annexure-6. Feeling aggrieved by the aforesaid action of the respondents, these writ petitions have been filed.

Learned counsel for petitioners submit that BPL Jeevan Raksha Kosh so as the NRHM Scheme are run by the State Government, hence, respondents should not make an effort to replace the petitioners by another set of contractual/ temporary employees with the same nature of employment as exist in favour of the petitioners. The endeavour of the respondents should be to continue all those who are required to undertake work under NRHM. The respondents were not required to issue a short term advertisement for filling up those posts under NRHM. It is prayed that a direction may be issued to maintain condition No.8 of the circular dated 9.8.2010 and, accordingly, impugned orders dated 4.2.2011 and subsequent order dated 10.2.2011 may be set aside. Respondents may accordingly be directed to adjust petitioners

सत्यमेव जयते
जयपुर
सही – प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक,
राज० उच्च न्यायालय पीठ,

under NRHM to the extent of requirement if, at all, certain posts have been reduced in BPL Jeevan Raksha Kosh.

Learned Advocate General, appearing for the State, submits that two different schemes have unnecessarily been mixed up by the petitioners. So far as NRHM is concerned, it was introduced by the Central Government some time in the year 2005 and it will exist till 31.3.2012. The NRHM is funded by the Government of India. Whereas, Chief Minister BPL Jeevan Raksha Kosh was introduced w.e.f. 1.1.2009. Thus, petitioners are having no right to seek continuation or appointment under NRHM. This is more so when the short term advertisement to fill up certain posts under NRHM was not acted upon, as such, no person has been given appointment under NRHM, thus, very basis of grievance of petitioner no more survives. In fact, no appointment have been given under NRHM pursuant to the short term advertisement dated 6.9.2010, rather respondents have taken a decision not to engage any person on contract basis or through placement agency. This is coming out from the circular dated 17.6.2011 at Annexure-R/7 issued by the State Government. For carrying out the work of BPL Jeevan Raksha Kosh, a further order was issued on 4.8.2011 at Annexure-R/8, wherein, assignment of work is allowed on 'job basis' i.e. a person is tasked to manage all the affairs which include to have the required accommodation and

सत्यमेव जयते
जयपुर
सही – प्रतिलिपि
प्रशासनिक अधिकारी न्यायिक,
राजस्थान उच्च न्यायालय पीठ,
जयपुर

other infrastructure with the work so that government is not required to incur further expenditure. Looking to it, various writ petitions were dismissed by this court which includes even dismissal of special appeal holding that a person, employed on contract basis, has no right for continuation.

Learned Advocate General admits that petitioners should not be replaced by another set of contractual/ temporary employees either by a direct contract or through placement agency. The government has already taken a decision not to engage fresh hands on contract basis even through placement agency. It has further been decided that no person would be replaced by another set of contractual/ temporary employee.

In fact, discontinuation had to be effected on account of reduction of stipulated funds in the scheme by the Government of India. As against expected funds of Rs.45 crore, only a sum of Rs.20 crore have been sanctioned under the scheme. Looking to lesser financial support to the scheme, respondents were left with no option but to reduce strength of the employees which was 1712 in the year 2009 but it has been reduced to 886 for the financial year 2010-11. Therefore, respondents may be given liberty to discontinue persons who are found in excess to the required strength. While doing so, respondents will maintain the principle

सत्यमेव जयते
जयपुर
सही – प्रतिलिपि

of 'last come – first go' at the block level. On account of reduction of requirement of employees, the respondents will remove only those candidates where scheme is closed in a particular block, thereby, whoever was engaged in that block, cannot be continued. If the scheme is continued in the block but with reduced strength, then person lastly appointed would first go. In the aforesaid circumstances, all these writ petitions may be disposed of with appropriate directions to redress grievance of petitioners. This is more so when withdrawal of condition No.8 of circular dated 9.8.2010 remains of no significance as the government has taken a decision not to engage fresh hands in NRHM pursuant to the short term advertisement thus question of shifting of surplus employees of BPL Jeevan Raksha Kosh Scheme in NRHM Scheme no more survives. In the aforesaid circumstances, respondents would be in a position to even maintain directions issued by the Division Bench of this court in the case of "Sardar Singh Jat & ors Versus State of Rajasthan & ors", DB Civil Special Appeal (Writ) No.589/2011, along with other connected appeals, decided on 10.5.2011.

Learned counsel for petitioners submit that they are in agreement with the learned Advocate General if the writ petitions are disposed of with appropriate directions as given out by the learned Advocate General.

In view of the facts and circumstances of the case and agreement shown by the learned counsel for parties, all these writ petitions are disposed of with the following directions/observations -

1. Respondents will not replace petitioners by another set of contractual/ temporary employees either by direct contract or through placement agency.

2. Petitioners would be continued in service till BPL Jeevan Raksha Kosh is continued but subject to requirement of their services. If the required strength is reduced, respondents would be at liberty to discontinue services of petitioners but it should be after following principle of 'last come – first go' at the block level where any of the petitioner is working. In case of withdrawal of the scheme from a particular block, respondents would be at liberty to discontinue services of the petitioners/persons working in that block and in case of continuance of scheme in the block but with reduction of strength, principle of 'last come – first go' would be applied at that block.

3. As agreed by respondents, they will not to make appointments under NRHM pursuant to short term advertisement

dated 6.9.2010, rather, they have agreed not to engage any one on contract basis by a direct contract or through placement agency. It can be only on 'job basis' and for which preference would be given to the existing persons if they are in position to undertake work on 'job basis'.

4. In future, if additional hands are required to undertake work of BPL Jeevan Raksha Kosh, the persons, who have been discontinued, would be given preference for appointment.

5. Petitioners, who have been taken under NRHM pursuant to interim order of this court, can be discontinued if additional hands are not required under NRHM as their continuance was pursuant to the interim order of this court only but, while doing so, respondents will take note of their previous engagement at the block level. If the BPL Jeevan Raksha Kosh is continued in his/ her block then such a candidate/petitioner would be considered based on principle of 'last come – first go'. If he is the person first appointed in comparison to other at the block level where the strength is reduced, then petitioner would be entitled to seek continuance on the principle of 'last come – first go'.

6. In future also, if there is further reduction in requirement of hands, respondents will apply the same formula of 'last come –

first go' at the block level for discontinuance of surplus hands as has been given above.

In view of disposal of the writ petitions, stay applications also stand disposed of.

(MN BHANDARI), J.

bnsharma

राजस्थान सरकार
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान राज्य स्वास्थ्य समिति
स्वास्थ्य भवन, जयपुर

क्रमांक : एफ29(37)/एनआरएचएम/एमएमजेआरके/उदयपुर/09/657 दिनांक 28/5/10.

स्वीकृति आदेश

वित्तीय वर्ष 2010–11 में मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना के तहत बीपीएल काउन्टर पर निम्नलिखित संविदाकर्मियों को लगाये जाने की स्वीकृति प्रदान की जाती है –

क्र. सं.	अस्पतालों का विवरण	अस्पतालों की संख्या	संविदा कार्मिको का विवरण			
			कम्प्यूटर मय ऑपरेटर	फार्मासिस्ट	लेखाकर्मी	योग
1	सवाई मानसिंह चिकित्सालय, जयपुर	1	9	6	2	17
2	मेडिकल कॉलेजों से संबंधित चिकित्सालयों	24	@6 144	@2 48	@1 24	216
3	जिला अस्पताल	33	@5 165	@1 33	@1 33	231
4	सैटेलाईट अस्पताल (6) सब डिविजनल अस्पताल (12)	18	@3 54	-	-	54
5	सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र	368	@1 368	-	-	368
	योग	444	740	87	59	886

उपरोक्त स्वीकृति निम्न शर्तों एवं दशाओं के तहत दी जा रही है –

1. वर्णित संविदा कार्मिकों का चयन चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग के पत्र क्रमांक प19(2)/चिस्वा/2/2009, दिनांक 29.01.2009 के बिन्दु संख्या 7 के अनुसार किया जावे।
2. संविदा कार्मिको को प्रतिमाह मानदेय की राशि वहीं दी जावेगी जिस राशि का उल्लेख इस विभाग के सम संख्यक स्वीकृति आदेश क्रमांक 3966, दिनांक 10.09.2009 में किया गया है।
3. कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (Man with Machine) को अधिकतम राशि 6000 रुपये प्रतिमाह तथा कम्प्यूटर ऑपरेटर को अधिकतम राशि 4500 रुपये प्रतिमाह का पारिश्रमिक दिया जावेगा।
4. इस विभाग के पूर्व सम संख्यक स्वीकृति आदेश क्रमांक 3966, दिनांक 10.09.2009 के अनुसार समस्त चिकित्सा संस्थानों द्वारा जितने कम्प्यूटर क्रय किये गये हैं उतने ही कम्प्यूटर ऑपरेटर रखते हुए शेष कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (Man with Machine) रखें जायेंगे।
5. मुख्यालय से पूर्व में एनआरएचएम के माध्यम से जो संविदाकर्मी लगाये गये है वे सभी इस योजना में पूर्व में दिये गये निर्देशानुसार कार्य करते रहेंगे।
6. इन संविदा कार्मिकों को देय मासिक पारिश्रमिक की राशि मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष योजना से वहन की जावेगी।

उपरोक्त संविदा कार्मिकों के स्वीकृति आदेश उप शासन सचिव, वित्त (व्यय – 1) विभाग के आई. डी. क्रमांक 101001873, दिनांक 25.05.2010 के क्रम में जारी किये गये हैं।

(डॉ. प्रीतम बी. यशवंत)
मिशन निदेशक
राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रषित है –

1. प्रमुख शासन सचिव, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, मुख्यमंत्री कार्यालय, सचिवालय, जयपुर।
2. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री, सचिवालय, जयपुर।
3. निजी सचिव, माननीय चिकित्सा एवं स्वास्थ्य राज्य मंत्री, सचिवालय, जयपुर।
4. निजी सचिव, मुख्य सचिव, राजस्थान सरकार, सचिवालय, जयपुर।
5. अतिरिक्त सचिव एवं मिशन निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, भारत सरकार, नई दिल्ली।
6. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
7. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा शिक्षा, सचिवालय, जयपुर।
8. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, जयपुर।
9. निजी सचिव, परियोजना निदेशक, आरएचएसडीपी, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
10. निजी सचिव, मिशन निदेशक राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, जयपुर।
11. निजी सचिव, विशिष्ठ सचिव (व्यय) वित्त विभाग, सचिवालय, जयपुर।
12. समस्त संभागीय आयुक्त, राजस्थान।
13. समस्त जिला कलक्टर, राजस्थान।
14. समस्त निदेशक, आईईसी/जन स्वास्थ्य/परिवार कल्याण/एड्स स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
15. परियोजना निदेशक, मुख्यमंत्री बीपीएल जीवन रक्षा कोष, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
16. परियोजना निदेशक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
17. वित्तीय सलाहकार, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
18. उप शासन सचिव वित्त (व्यय – 1) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
19. समस्त अधीक्षक, मेडिकल कॉलेज चिकित्सालय एवं संबंधित चिकित्सालय, राजस्थान।
20. समस्त क्षेत्रीय संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, राजस्थान।
21. समस्त मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, राजस्थान।
22. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, जिला अस्पताल, राजस्थान।
23. लेखाधिकारी, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य (ग्रुप 2) विभाग, सचिवालय, जयपुर।
24. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सब डिविजन चिकित्सालय, राजस्थान।
25. समस्त प्रमुख चिकित्सा अधिकारी, सैटेलाईट चिकित्सालय, राजस्थान।
26. समस्त ब्लॉक सीएमएचओ, राजस्थान।
27. समस्त चिकित्सा अधिकारी इन्चार्ज सामु0 स्वा0 केन्द्र, राजस्थान।
28. सलाहकार (एचआरडी) राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर।
29. समस्त जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राजस्थान।
30. इन्चार्ज सर्वर रुम, राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, स्वास्थ्य भवन, जयपुर को भेजकर लेख है कि कृपया संबंधित को ई–मेल करवाने की कार्यवाही की जावे।
31. रक्षित पत्रावली।

27/5/10
(जे0पी0 मीना)
परियोजना निदेशक
मुख्यमंत्री जीवन रक्षा कोष